

गौर कीजिएगा:- चाय की टपरी पर बैठे एक सज्जन ने एकदम सही बात कही

विनोद बंसल

नई दिल्ली। लगातार 10 सालो से अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार उत्तर भारत के प्रदूषण पर जानबूझ कर एक गलती कर रहे है, और वो है "उसे स्वीकार करना और उस पर प्रतिक्रियाए देना व उसको कम करने के लिए प्रयास करना"

कोरोना के समय भी उन्होंने यह गलती की थी ! दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद,

फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा, पानीपत व अन्य कई शहरों में भी भयंकर प्रदूषण है, लेकिन इस बार भी दिल्ली की मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आ गई जबकि अन्य पड़ोसी प्रदेशों के सीएम घर में हैं, ना दिख रहे है ना मीडिया में है। ना ही प्रदूषण पर ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं !

दिल्ली के बच्चो के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि नोएडा फरीदाबाद गाजियाबाद

गुरुग्राम में सारे स्कूल बंदिया खुले हैं, वहाँ बच्चे जा रहे हैं, उनके फेफड़े लोहे के हैं शायद ?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मीडिया से बात कर रहे हैं, जबकि वाकी के राज्य के पर्यावरण मंत्री कौन हैं छोड़िए, देश का पर्यावरण केंद्रीय मंत्री कौन है यह तक किसी को नहीं पता ?

असल में हर साल बड़ी होशियारी से उत्तर भारत की प्रदूषण समस्या को दिल्ली की प्रदूषण

समस्या बना दिया जाता है और देश की मासूम खासकर उत्तर भारत प्रदेशों की जनता इसे सिर्फ दिल्ली की समस्या मानकर अपने राज्यों की सरकारो से कोई सवाल नहीं करती और बेखोफ जान लेवा प्रदूषित हवा में घूमती रहती है क्योंकि प्रदूषण तो सिर्फ दिल्ली में ही फ़सा है !

क्या है कारण ? दिल्ली सरकार का प्रदूषण के लिए इतना ख़ौफ़ उत्पन्न करने का, सोच/ समझें।

दिल्ली का सविदा कर्मचारी करेगा चक्का जाम

दिल्ली मे सविधान के मौलिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन

अन्याय शोषण भ्रष्टाचार

संविदा कर्मचारियों की मांग 60 वर्ष जॉब सिक्योरिटी लागू करो सामान काम का सामान वेतन लागू करो

निवेदक:- दिल्ली का समस्त संविदा कर्मचारी एवं मजदूर

सोशल मीडिया, सरकार विधायक, मंत्री, सांसद एवं माननीय कोर्ट तक अपनी बात को शेयर करें

आर्टिकल 14,16,21 और 39डी

वर्षों तक नौकरी करवा कर नौकरियों से निकला जा रहा है जैसे ही मजदूर अपने हक मांगता है सरकार मजदूर को नौकरी से निकाल रही है

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली-NCR से अगले आदेश तक नहीं हटेगा GRAP-4; स्कूलों को बंद करने के निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर में ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को तुरंत टीमों का गठन कर आवश्यक निगरानी कार्य करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को ग्रेप-4 के तहत आवश्यक निगरानी कार्यों के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने 12वीं तक के स्कूल बंद करने को कहा।

जस्टिस अब्ध एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। पीठ ने कहा, रहम GRAP-4 के तहत प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्देश देते हैं, भले ही एक्ज्यूआई स्तर 450 से नीचे चला जाए।

प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की दें जानकारी: SC

सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे ग्रेप-4 में बताए गए सभी उपायों पर तुरंत विचार करें और सुनवाई की अगली तारीख से पहले उठाए गए सभी कदमों की जानकारी दें।

दिल्ली और एनसीआर सरकारों को ग्रेप-4 के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करने को कहा।

अगले आदेश तक दिल्ली-NCR में ग्रेप-4 लागू रहेगा: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक

ग्रेप-4 दिल्ली और एनसीआर में लागू रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। सभी राज्य और केंद्र सरकारों को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेप चरण 3

दिल्ली में ग्रेप 4 लागू होने के बाद भी खुले हुए हैं स्कूल....

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं पर यहां दिल्ली में ग्रेप 4 लागू होने के बाद भी स्कूल खुले हुए हैं दिल्ली सभी शिक्षक रोज स्कूल बुलाए जा रहे हैं जिनके दो लाख वाहन रोज प्रदूषण बढ़ाते हैं। स्कूल बंद का मतलब

यहां अधिकारियों द्वारा कुछ और लगाया जा रहा है उनके हिसाब से जब वे ऑफिस आ रहे हैं तो शिक्षकों को भी स्कूल आना चाहिए। उन्होंने यह समझ नहीं आ रहा है कि जब स्कूलों में छात्र नहीं हैं तो शिक्षकों का क्या कार्य है ऑनलाइन शिक्षण तो शिक्षक घर से भी करवा सकते हैं जैसे कोरोना काल में

कराया गया था। शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए जाए जिससे 2 लाख शिक्षकों के वाहन कम निकलें दिल्ली में। शिक्षकों के भी स्वास्थ्य की चिंता दिल्ली सरकार को करनी चाहिए।

कुलदीप सिंह खत्री, अध्यक्ष शिक्षक न्याय मंच नगर निगम

गैस चैंबर बनी दिल्ली: घर से बाहर निकलें तो पहनें N95 मास्क, कई इलाकों में शाम 7 बजे भी AQI 900 पार

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली की हवा दम घोट रही है। गैस चैंबर बनी दिल्ली में सांस लेने के लिए मास्क लगाना जरूरी हो गया है। चिकित्सक घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। सोमवार को शाम सात भी एक्ज्यूआई (AQI) कई जगहों पर 900 के पार था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों और युवाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए दिल्ली की हवा खतरनाक है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा जहरीली बनी हुई है। ग्रेप का चौथा चरण लागू है, लेकिन वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, जहां शाम को 4 से 5 बजे के बीच एक्ज्यूआई 1000 के पार रहा या आसपास रहा।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एक्ज्यूआई खतरनाक स्तर यानी 450 से ऊपर ही है।

दिल्ली में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। दिल्ली के अस्पतालों में सांस लेने में दिक्कत और गले में जलन जैसे परेशानी वाले मरीज भी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। स्वास्थ्य सलाहकार लोगों को एन95 मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। इसके अलावा बिना जरूरी काम के घर से

दिल्ली की हवा 'जहरीली' मास्क पहनना जरूरी

बाहर न जालने की सलाह दी गई है। दिल्ली में फिलहाल जितना एक्ज्यूआई रह रहा है, उससे सांस और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।

दिल्ली में कहा सबसे ज्यादा एक्ज्यूआई

दिल्ली में सोमवार (18 नवंबर) शाम सात बजे एक्ज्यूआई गंभीर श्रेणी से लेकर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आनंद विहार में एक्ज्यूआई 936, जहांगीरपुरी में 871, मंदर डेयरी में 908, मुंडका में 839, नई दिल्ली में 731, ग्रीन पार्क में 706,

मंदिर मार्ग में 746, पंजाबी बाग में 809, इहबास में 915, दर्ज किया गया। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक्ज्यूआई 1176 एनसीआर में फिलहाल सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है।

सतर्क रहने की बहुत जरूरत

सर गंगा राम अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. उज्ज्वल पारख ने कहा कि लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। हर किसी को जितना संभव हो सके बाहर निकलने

से बचना चाहिए। अगर उन्हें बाहर जाना ही है तो वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए। मास्क एन95 ज्यादा कारगर है।

उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने और HEPA-फिल्टर एयर प्यूरीफायर का उपयोग करने की सलाह दी।

पारख ने कहा कि हाइड्रोटेड रहने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पीना भी जरूरी है। फेफड़ों की बीमारियों वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी दवाओं का नियमित सेवन करना चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप (GRAP 4 Implement) का चौथा चरण लागू है। इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें निजी और सरकारी निर्माण कार्य और खनन के कार्य पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा दिल्ली में बीएस-4 डीजल और बीएस-3 पेट्रोल वाहनों के प्रवेश पर रोक है। साथ ही ट्रकों की एंटी पर बैन है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं।

दिल्ली का AQI

दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी मुंडका आनंद विहार मंदिर मार्ग नई दिल्ली इहबास पंजाबी बाग मंदर डेयरी ग्रीन पार्क

एक्ज्यूआई 871 839 936 746 731 915 809 908 706

(शाम 7 बजे, 18 नवंबर)

Source - aqi.in

प्रदूषण के कारण दिल्ली में बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे एस्ट्रॉयड, इनहेलर लेने को मजबूर

सुषमा रानी

नई दिल्ली। पूरे उत्तर भारत में पराली जलने से बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना दुश्चारा हो गया है। बच्चे-बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन भाजपा शासित केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। भाजपा शासित केंद्र सरकार के इस लापरवाह रवैये को सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा करते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि, देश में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन भाजपा शासित केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धारे बैठी है। प्रदूषण के कारण बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे एस्ट्रॉयड, इनहेलर लेने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पिछले 6-7 सालों में लगातार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

सीएम आतिशी ने कहा कि, "आज दिल्ली के सवाल पूछते हुए कहा कि, अगर पंजाब सरकार पराली जलाने की घटनाओं को 80% तक कम कर सकती है तो बाकी राज्य क्यों नहीं? क्यों पूरे उत्तर भारत को मेडिकल इमरजेंसी की ओर धकेल दिया गया है? केंद्र सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति क्यों कर रही है? पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है?

उन्होंने कहा कि, भाजपा शासित केंद्र राजनीति करना बंद करें और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पराली जलाने की घटनाओं पर रोकथाम लागू।

सीएम आतिशी ने कहा कि, "आज दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। मेरी दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कल रात भर मुझे लोगों के फ़ोन आते रहे। किसी को अपने बुजुर्ग माता-पिता को

भाजपा पिछले 10 साल से...!', कैलाश गहलोत के BJP में शामिल होने के बाद केजरीवाल ने लगाए गंभीर आरोप

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पदाधिकारी सम्मेलन के दौरान दक्षिणी दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मंडल प्रभारियों से हर बूथ जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 10 साल से हमारी पार्टी को तोड़ने में लगी है लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पदाधिकारी सम्मेलन के तरह दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मंडल प्रभारियों से बात कर हर बूथ जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भगवान आप के साथ हैं और इस बार भी हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का चुनाव जीतेगे।

आप सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत द्वारा मंत्री पद के साथ पार्टी छोड़ देने के एक दिन बाद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वाले अपनी सारी ताकत लगाकर पिछले दस साल से हमारी पार्टी तोड़ने में लगे हैं। मगर उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। इसके साथ ही केजरीवाल ने फिर दोहराया कि उनकी पत्नी, बच्चे,

सरस आजीविका मेला में ग्रामीण महिलाओं ने किया है रचनात्मकता का अद्वितीय प्रदर्शन



सुषमा रानी

नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित 43वें विश्व व्यापार मेले के हॉल नंबर 9 और 10 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा समर्थित सरस आजीविका मेला 2024 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासाानी ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं ने रचनात्मकता का अद्वितीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि यह मेला ग्रामीण भारत की महिलाओं के आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। डॉ. पेम्मासाानी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि सरस आजीविका मेला न केवल ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का मंच प्रदान करता है, बल्कि उन्हें बेहतर विपणन और पैकेजिंग तकनीकों में भी परिणत बनाता है। यह मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'लखपति दीदी' अभियान को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है और 'आत्मनिर्भर भारत' तथा 'वोकल फॉर लोकल' जैसी सरकारी पहलों का उत्कृष्ट उदाहरण है।"

इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय



दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मतलब 49 सिगरेट पीने जैसा...

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि एन95 मास्क पहनना जरूरी हो गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां एक्यूआई 100 के आसपास रह रहा है। दिल्ली में कई इलाकों में सांस लेना मतलब सिगरेट पीने जैसा है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एनसीआर में 10वीं और 12वीं को छोड़कर कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली के कई इलाके हैं, जो रेड जोन में हैं। वह एक्यूआई 1000 के ऊपर या आसपास है। ऐसे इलाकों में स्वास्थ्य सलाहकार मास्क लगाकर बाहर निकलने या घर से न निकलने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली में कई इलाकों में सांस लेना मतलब सिगरेट पीने जैसा है। राष्ट्रीय राजधानी में सबसे

साँस लेने की दिक्कत के कारण अस्पताल में एडमिट करवाना था तो किसी पेरेंट को अपने छोटे-छोटे बच्चे को देर रात एस्ट्रॉयड के इनहेलर दिलावाना था।"

उन्होंने कहा कि, र्प्रदूषण के कारण बुजुर्ग साँस नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। बच्चे साँस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों को एस्ट्रॉयड, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देशभर में पराली जल रही है। एक एक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आज हर राज्य में पराली जलाई जा रही है और केंद्र

खराब स्थिति 1023 के AQI पर है, जहां एक व्यक्ति प्रतिदिन 49 सिगरेट पीने के बराबर है।

मास्क पहनना हुआ जरूरी
यूसीएमएयर और जीटीबी अस्पताल में सामुदायिक चिकित्सा के रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रजत शर्मा ने कहा प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि एन95 मास्क पहनना जरूरत बन गई है। स्वस्थ व्यक्ति भी सांस से संबंधित बीमारियों का शिकार हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि सर्जिकल या कपड़े के मास्क नहीं पहनना है। इस हालात में एन95 मास्क बेहतर उपाय है।

शाम पांच बजे एनसीआर का एक्यूआई
शाम को पांच बजे के समय गाजियाबाद का एक्यूआई 603 दर्ज किया गया, जबकि वसुंधरा इलाके का 1176 दर्ज किया गया। गुरुग्राम का 608

सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।"

सीएम आतिशी ने कहा कि, "आज पूरे उत्तर भारत को मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, राजस्थान में बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो। आज पूरे देश में वायु की गुणवत्ता (एक्यूआई) बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में है

सीएम आतिशी ने कहा कि, "यदि पराली जलाने की घटनाएं देखे तो हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान हर जगह पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।"

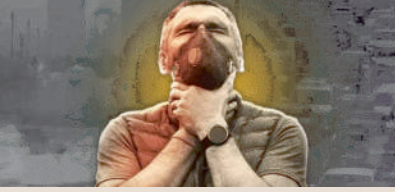
अरविंद केजरीवाल ने सक्रिय राजनीति करने वाले राघवेंद्र शौकीन के नाम पर लगाई मुहर : मनीष सिसोदिया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली में जाट समाज के लोकप्रिय नेता राघवेंद्र शौकीन सीएम आतिशी की कैबिनेट में नए मंत्री होंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राघवेंद्र शौकीन के नाम पर मुहर लगा दी है। इस बाबत जानकारी साझा करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बताया कि राघवेंद्र शौकीन जाट समुदाय के लोकप्रिय नेता हैं और वह दिल्ली देहात में सक्रिय राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। अरविंद केजरीवाल की पट्टी-लिखी टीम में राघवेंद्र शौकीन सिविल इंजीनियर हैं। राघवेंद्र शौकीन नांगलोई जाट से दूसरी बार विधायक हैं, जबकि दो बार पार्षद भी रह चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वह दिल्ली के लोगों की खूब सेवा करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाएंगे।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर आप नेता राघवेंद्र शौकीन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली को एक नया कैबिनेट मंत्री मिल रहा है अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि

दिल्ली में सांस लेना मतलब रोजाना 49 सिगरेट पीना



और आर्य नगर इलाके का एक्यूआई 1023 दर्ज किया गया। फरीदाबाद का 475 और नोएडा का एक्यूआई 459 दर्ज हुआ।

कहां सबसे ज्यादा एक्यूआई (समय साढ़े 4 बजे)

दिल्ली में शाम को साढ़े चार बजे मंदिर मार्ग इलाके का एक्यूआई 1063 दर्ज किया गया।

उन्होंने कहा कि, रूपूरे देश में कोई राज्य है जिसने पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है तो वो पंजाब है। ऑफ़िडे देखे तो पंजाब में जहाँ 2021 में पराली जलाने की 73,300 घटनाएँ हुई थी वो घटकर पिछले साल तक 36,650 हो गया और इस साल तक जब तकरीबन 90% तक पराली जलाने की घटनाएँ हो चुकी है, पंजाब में मात्र 8404 पराली जलाने की घटनाएँ हुई हैं।"

उन्होंने साझा किया कि, र्वही दूसरी तरफ़ अन्य राज्यों के आंकड़े देखे तो उत्तर प्रदेश में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाएँ 60% बढ़ी है। जहाँ पिछले साल पराली जलाने की 1533

अरविंद केजरीवाल ने सक्रिय राजनीति करने वाले राघवेंद्र शौकीन के नाम पर लगाई मुहर : मनीष सिसोदिया



राघवेंद्र शौकीन, मुख्यमंत्री आतिशी की कैबिनेट में मंत्री होंगे। हम सब जानते हैं कि राघवेंद्र शौकीन जाट समुदाय के एक लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। जिस तरह आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यह पढ़े-लिखे लोगों की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल खुद पढ़े-लिखे हैं, और

मुंडका में 1023, गुरुग्राम के आर्य नगर में भी 1023 एक्यूआई, जहांगीरपुरी में 1003, पंजाबी बाग में 911, इहबास में 945 और आनंद विहार में 956 दर्ज किया गया। नई दिल्ली में एक्यूआई 805 बना दर्ज किया। दिल्ली के सभी इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू
दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू है। इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें निजी और सरकारी निर्माण कार्यों और खनन के कार्यों पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा दिल्ली में बीएस-4 डीजल और बीएस-3 पेट्रोल वाहनों के प्रवेश पर रोक है। साथ ही ट्रकों की एंटी पर बैन है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं।

घटनाएँ हुई वो इस साल बढ़कर 1926 हो गई। राजस्थान में भी पराली जलाई जा रही है। 2020 में राजस्थान में पराली जलाने की सिर्फ 430 घटनाएँ सामने आईं वहीं इस साल ये बढ़कर 1926 पहुँच गया है। और आज देशभर में कहीं सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है तो वो मध्य-प्रदेश में जलाई जा रही है। यहाँ 15 सितंबर से 17 नवंबर तक पराली जलाने की 9,600 घटनाएँ हुई है यानी रोज 700 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है। यही कारण है कि, मध्य प्रदेश के शहरों में हवा की गुणवत्ता देखे तो वो भी बहुत गंभीर श्रेणी में पहुँच गए हैं।"

सीएम आतिशी ने कहा कि, आज मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूँ कि, देशभर में पिछले 6-7 साल से पराली जलाना बढ़ता जा रहा है, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान। पिछले 6-7 साल में केंद्र सरकार एक कदम बताए जो उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए उठाया।"

उन्होंने कहा कि, "अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने की घटनाओं को 80% तक कम कर सकती है तो बाकी राज्यों में ये क्यों बढ़ रही है? क्यों पूरे उत्तर भारत को मेडिकल इमरजेंसी की ओर धकेल दिया गया है? आज पूरे उत्तर भारत में चाहे हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के किसी भी राज्य के किसी भी शहर के के किसी भी अस्पताल में जाए तो वहाँ बुजुर्ग-छोटे बच्चे एडमिट दिखेंगे क्योंकि उन्हें साँस लेने में मुश्किल हो रही है।"

सीएम आतिशी ने कहा कि, रक्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है? आज मैं भाजपा शासित केंद्र से अपील करना चाहती हूँ कि, पराली का धुआँ राज्यों की सीमाओं को नहीं देखता, किसी पार्टी को या उसके समर्थक को नहीं देखता। हर राज्य में हर बुजुर्ग-हर बच्चे को साँस लेने में दिक्कत हो रही है चाहे वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो।"

उन्होंने कहा कि, र ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है जब देशभर में पराली जलाने से मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं तो केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा और कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए भाजपा राजनीति करना बंद करें और सामने आकर उत्तर भारत के सभी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएँ कम करें।

गैस चैंबर बनी दिल्ली: घर से बाहर निकलें तो पहनें N95 मास्क, कई इलाकों में शाम 7 बजे भी AQI 900 पार

दिल्ली की हवा दम घोंट रही है। गैस चैंबर बनी दिल्ली में सांस लेने के लिए मास्क लगाना जरूरी हो गया है। चिकित्सक घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। सोमवार को शाम सात भी एक्यूआई (AQI) कई जगहों पर 900 के पार था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों और युवाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए दिल्ली की हवा खतरनाक है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा जहरीली बनी हुई है। ग्रेप का चौथा चरण लागू है, लेकिन वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, जहां शाम को 4 से 5 बजे के बीच एक्यूआई 1000 के पार रहा या आसपास रहा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर यानी 450 से ऊपर ही है। दिल्ली में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। दिल्ली के अस्पतालों में सांस लेने में दिक्कत और गले में जलन जैसे परेशानी वाले मरीज भी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। स्वास्थ्य सलाहकार लोगों को एन95 मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, ताकि प्रदूषण से बचा जा सके।

इसके अलावा दिना जरूरी काम के घर से बाहर न जालने की सलाह दी गई है। दिल्ली में फिलहाल जितना एक्यूआई रह रहा है, उससे सांस और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।

दिल्ली में कहां सबसे ज्यादा एक्यूआई
दिल्ली में सोमवार (18 नवंबर) शाम सात बजे एक्यूआई गंभीर श्रेणी से लेकर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आनंद विहार में एक्यूआई 936, जहांगीरपुरी में 871, मंदर डेयरी में 908, मुंडका में 839, नई दिल्ली में 731, ग्रीन पार्क में 706, मंदिर मार्ग में 746, पंजाबी बाग में 809, इहबास में 915, दर्ज किया गया। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक्यूआई 1176 एनसीआर में फिलहाल सबसे



दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर डॉक्टर ने चेताया, घर से बाहर निकलना हो सकता है खतरनाक; पढ़ें बचाव के उपाय

सर गंगा राम अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. उज्ज्वल पारेख ने इस बात पर जोर दिया कि इस समय लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। र किसी को जितना संभव हो सके बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए और अगर बाहर जाना ही पड़े तो वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए।

नई दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सोमवार को 'गंभीर खतरा' श्रेणी में पहुंचने और इस गैसमय के सबसे खराब स्तर पर पहुंचने के कारण डॉक्टरों ने इसके स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है। इसके साथ ही डॉक्टर ने आग्रह किया कि जहरीली हवा से बचने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए। डॉक्टरों ने दिल्लीवासियों को बाहरी गतिविधियों को कम करने, हाइड्रेट रहने और इनडोर पार्टिकुलेट मैटर को कम करने के लिए HEPA फिल्टर वाले वायु शोधक का उपयोग करने की सलाह दी। डॉक्टरों ने बताया किन लोगों को पहले से फेफड़े या दिल की बीमारियां हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए और अपनी दवाएं लेते रहना चाहिए।

कई जगहों पर एक्यूआई 500 के पार : दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 484 के साथ एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई और दोपहर। बजे तक और खराब सेकंड 490 से गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, द्वारका सेक्टर 8, नजफगढ़, नेहरू नगर और गुंडका सहित कुछ निगमानी रेसर्गनो ने अधिकतम AQI स्तर 500 दर्ज किया।

स्वस्थ व्यक्ति भी से सकता है बीमार : रजत शर्मा ने कहा, "वायु प्रदूषण का जो गंभीर स्तर हम देख रहे हैं, उसके लिए तत्काल सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए मास्क का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। यह अब केवल सेवेदनशील लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी के लिए जोखिम भरा हो सकता है।"

घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें: डॉ. उज्ज्वल पारेख

सर गंगा राम अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. उज्ज्वल पारेख ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। र किसी को जितना संभव हो सके बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए और अगर बाहर जाना ही पड़े तो वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए।

ज्यादा दर्ज किया गया है।
सतर्क रहने की बहुत जरूरत
सर गंगा राम अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. उज्ज्वल पारेख ने कहा कि लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। हर किसी को जितना संभव हो सके बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर उन्हें बाहर जाना ही है तो वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए।



चाहिए। मास्क एन95 ज्यादा कारगर है।
उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने और HEPA-फिल्टर एयर प्यूरीफायर का उपयोग करने की सलाह दी। पारेख ने कहा कि हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पीना भी जरूरी है। फेफड़ों की बीमारियों वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी दवाओं का नियमित सेवन करना चाहिए।



प्रचार का शोर थमा, निगम की टीम ने हटाए बैनर-पोस्टर; 20 नवंबर को 507 बूथों पर डाले जाएंगे वोट

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है और नगर निगम की टीम ने बिना अनुमति लगे पोस्टर और बैनर हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता उपाय किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके।

गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सोमवार शाम पांच बजे प्रचार का शोर थम गया है। इसके साथ ही नगर निगम की टीम ने बिना अनुमति के लगाए पोस्टर, बैनर हटाने का अभियान शुरू कर दिया है।

छह माह पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाकर चुनाव के मैदान में उतारा। अतुल गर्ग ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद



विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चुनाव के मैदान में कुल 14 प्रत्याशी हैं और सबने मतदाताओं को साधने के लिए हरसंभव प्रयास किया।

23 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित

अब 20 नवंबर को मतदान होना है। अधिक से अधिक मतदाता मतदान करें, जिससे कि चुनाव में मतदान प्रतिशत बेहतर हो। इसके लिए घर-घर जाकर लोगों से मतदान की अपील प्रत्याशी और उनके समर्थक करेंगे। 23 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उप जिला

निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जाएगा।

507 बूथों पर मताधिकार का होगा प्रयोग

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को कमला नेहरू नगर से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया

जाएगा। 507 बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान कर सकेंगे। उपचुनाव के मद्देनजर लगभग तीन हजार अधिकारियों और कर्मचारियों की इयूटी लगाई गई है। कमला नेहरू नगर स्थित पोलिंग पाटी रवानगी स्थल पर टेंट लगाया गया गया है, बैरिकेडिंग की गई है।

ईवीएम-वीवीपैट को लेकर मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा

सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंगलवार को पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और वीवीपैट को लेकर मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा, मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों के रुकने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि बुधवार को होने वाले उपचुनाव में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूल बंद, 20 नवंबर को रहेगा अवकाश



गाजियाबाद जिले में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी क्योंकि यह उपचुनाव के मद्देनजर फैसला लिया गया है। वहीं 20 नवंबर को स्कूलों का अवकाश रहेगा क्योंकि गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट (Ghaziabad Upchunav) पर उपचुनाव होने को है। प्रदूषण को लेकर अभी तक कोई आदेश जानी नहीं किया गया है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी, क्योंकि यह उपचुनाव के मद्देनजर फैसला लिया गया है। वहीं, 20 नवंबर को स्कूलों का अवकाश रहेगा, क्योंकि गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने को है। प्रदूषण को लेकर अभी तक कोई आदेश जानी नहीं

किया गया है। उपचुनाव के मद्देनजर गाजियाबाद शहर के 12वीं तक के स्कूलों में मंगलवार को ऑनलाइन क्लासेज होंगी, 20 नवंबर (बुधवार) को मतदान के मद्देनजर जिले में सार्वजनिक अवकाश है। ऐसे में बुधवार को जिले में स्कूलों के साथ ही सभी औद्योगिक इकाइयों और सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा।

स्कूल वाहन रहेंगे व्यस्त जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि उपचुनाव में स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया गया है। स्कूली वाहनों को पोलिंग पार्टियों की रवानगी और उनको मतदान संपन्न होने के बाद वापस लेकर आने के लिए लगाया गया है। इस वजह से 12वीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी, विद्यार्थी स्कूल नहीं जाएंगे। 20 नवंबर को जिले में सार्वजनिक अवकाश है।

बिजली चोरी करने पर 9.81 का लाख जुर्माना, अदालत ने खारिज की उपभोक्ता की अपील

अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में बिजली निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है। उपभोक्ता पर 9.81 लाख रुपये की चोरी का आरोप था। अदालत ने उपभोक्ता द्वारा दायर केस को खारिज कर दिया। बिजली निगम ने उपभोक्ता को नोटिस जारी किया था जिसके बाद उपभोक्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आगे जानिए आखिर पूरा मामला क्या है।

गुरुग्राम। हरियाणा के बादशाहपुर में एक उपभोक्ता पर 9.81 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उपभोक्ता ने इस मामले में बिजली विभाग के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, अब इस मामले में उपभोक्ता की ओर से दायर अपील को अदालत ने खारिज कर दिया गया है।

बता दें कि सिविल जज (जूनियर डिबिजन) मनजोत कौर की अदालत ने बादशाहपुर बिजली निगम के उपभोक्ता पर बनाए गए 9.81 लाख रुपये की चोरी के केस को सही करार दिया है। अदालत ने उपभोक्ता के बिजली निगम के विरुद्ध दायर केस को खारिज कर दिया। वहीं, कोर्ट द्वारा अपील खारिज खरने से उपभोक्ता को



इटका लगा है।

उपभोक्ता पर बनाया था चोरी का केस

वहीं, बिजली निगम की तरफ से अदालत में पैरवी अधिवक्ता बीपी शर्मा ने की। बिजली निगम ने सेक्टर-17 की रहने वाली बिजली उपभोक्ता अनुपमा कुमारीया के दरबारीपुर रोड पर बिजली कनेक्शन से चोरी करने का केस बनाया था।

बिजली चोरी करते पकड़ा गया था उपभोक्ता

सेक्टर-17 की रहने वाली अनुपमा कुमारीया का दरबारीपुर रोड पर एक बिजली कनेक्शन चल रहा था। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण की विजिलेंस टीम के एसडीओ प्रमोद कुमार ने 21 नवंबर 2022 को दरबारीपुर रोड स्थित अनुपमा कुमारीया के बिजली मीटर को चेक किया। बिजली निगम ने उस समय डायरेक्ट केबल डालकर बिजली चोरी करते पकड़ा गया।

उपभोक्ता पर लगाया था

9.81 लाख का जुर्माना बादशाहपुर बिजली निगम के एसडीओ ने उपभोक्ता अनुपमा कुमारीया को 9.81 लाख रुपये का नोटिस थमाया। अनुपमा कुमारीया के बेटे भवनीश कुमारीया ने बिजली निगम के इस चोरी के केस को अदालत में चुनौती दी।

छापेमारी के दौरान कराई थी वीडियो ग्राफी

बिजली निगम के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने बताया कि जिस समय छापेमारी की गई थी। उस समय पूरी वीडियो ग्राफी की गई थी। मौके से चोरी में प्रयोग की जाने वाली बिजली केबल आदि भी बरामद की गई थी। मौके पर आकाश नामक व्यक्ति मौजूद था। चेंकिंग रिपोर्ट पर आकाश के हस्ताक्षर भी कराए गए थे।

बिजली निगम के एसडीओ को बनाया था पार्टी

उपभोक्ता ने इस मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सोहना डिबिजन के कार्यकारी अभियंता, सर्कुलर टूके अधीक्षण अभियंता और बादशाहपुर बिजली निगम के एसडीओ को पार्टी बनाया था।

चोरी के केस को सही पाया गया

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बिजली निगम के चोरी के केस को सही पाया। वादी भवनीश कुमारीया के केस को डिसमिस कर दिया।

सिपाही की वर्दी फाड़ी, म्यूजिक सिस्टम बंद कराने पहुंची थी पुलिस; सबूतों के अभाव में 3 आरोपी बरी

गुरुग्राम के बादशाहपुर में पुलिस की वर्दी फाड़ने और मारपीट करने के आरोपित को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बताया गया कि पुलिस को तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान आरोपितों ने पुलिस के साथ हाथपाई व सिपाही की वर्दी फाड़ दी थी।

ग्रेटर नोएडा। गुरुग्राम के बादशाहपुर के अर्जुन नगर में तेज आवाज में बज रहे म्यूजिक सिस्टम को बंद करने पहुंचे पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ने और मारपीट करने के तीन आरोपित अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिए। आरोपितों की पैरवी अधिवक्ता सन्नी तंवर ने की।

एक आरोपित की हो गई थी हत्या बताया गया कि एक आरोपित की पिछले साल हत्या हो गई थी। अर्जुन नगर पुलिस चौकी ने हेड कॉन्स्टेबल सुग्रीम को शिकायत पर

आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।

रात में गश्त पर थे हेड कॉन्स्टेबल और सिपाही

हेड कॉन्स्टेबल सुग्रीम ने अर्जुन नगर पुलिस चौकी में 4 फरवरी 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को नामजद किया था। पुलिस का आरोप था कि हेड कॉन्स्टेबल सुग्रीम और सिपाही जितेंद्र रात करीब एक बजे गश्त पर थे।

तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने की मिली थी शिकायत

इस दौरान उन्हें अर्जुन नगर की गली नंबर 5 में तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने की शिकायत मिली। वह मौके पर पहुंचकर म्यूजिक सिस्टम बंद करने की कह रहे थे। इसी दौरान राजेश मेघराज, नितिन, दीपक उनसे बहस करने लगे।

मारपीट के दौरान फाड़ी थी सिपाही की वर्दी

हाथपाई करते हुए वे लोग कहने लगे कि

नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर किसानों ने जड़ ताला, गेट के बाहर धरने पर बैठे

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पर किसानों ने ताला जड़ दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्राधिकरण गेट के बाहर किसानों ने डेरा डाल लिया है और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यह धरना भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले किया जा रहा है।



बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट का आदेश मनमानी पर अंकुश

बुलडोजर एक्शन में यही बात नजर आती है। दरअसल यह काम देश की अदालतों का है कि सुनवाई के बाद आरोपी को सजा देने या नहीं देने का। बुलडोजर एक्शन में ऐसे न्याय की संभावना पहले ही खत्म हो जाती है, जहां बगैर किसी सुनवाई के फैसला सुना दिया जाता है।

सरकारों की गलतफहमी है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें मनमानी का अधिकार मिल जाता है। इसी भ्रम में सरकारें अपने को अदालत से ऊपर समझने लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामले में फैसला देकर सरकारों का यह सपना तोड़ दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली की आप सरकार के मामले में दिया है, किन्तु यह लागू सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए तीखी टिप्पणी की। साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन तय कर दी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दो टूक कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिन्द बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित सभ से दो टूक कहा है कि इस मामले में मनमानी रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। यद्यपि यह फैसला दिल्ली सरकार से संबंधित है पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस फैसले के बाद अब योगी सरकार के लिए बुलडोजर एक्शन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कार्यपालिका के पास असीम शक्तियां होती हैं। इसी बल पर हर साल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कार्यपालिका विभिन्न

कारणों को आधार बनाकर सैकड़ों आदेशों का अनुपालन नहीं करती है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन का यह सिलसिला पूरे देश में फैल गया था। राज्यों की सरकारों ने इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने में कसर बाकी नहीं रखी। वोट बैंक राजनीति ऐसे फैसलों में साफ नजर आती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन अपराधियों के आवास और व्यवसायिक प्रतिष्ठान गिराने के लिए लिया गया था। बुलडोजर एक्शन में भी अपराधियों में भेदभाव के उदाहरण मौजूद हैं। इसका दुरुपयोग भी सांप्रदायिक आधार पर किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी सख्त कार्रवाई से अपराधियों में कहीं न कहीं खौफ उत्पन्न होता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरह माफिया या गैंगस्टर का सफाया किया, उससे काफी हद तक अपराधों पर लगाम लग सकी है। इस कार्रवाई से शायद ही कोई इतफाक रखता हो। सवाल यही आता है कि अपराध रोकने की आड़ में सरकार क्या कानून से ऊपर है।

बुलडोजर एक्शन में यही बात नजर आती है। दरअसल यह काम देश की अदालतों का है कि सुनवाई के बाद आरोपी को सजा देने या नहीं देने का। बुलडोजर एक्शन में ऐसे न्याय की संभावना पहले ही खत्म हो जाती है, जहां बगैर किसी सुनवाई के फैसला सुना दिया जाता है। इससे यदि आरोपी गलत ना भी हो तो उसे घर या दुकान तुड़वाने की सजा भुगतनी पड़ती है। जबकि सजा तय करने की जिम्मेदारी अदालतों की है। सरकारों की यह हरकत निश्चित तौर पर अदालतों के मामले में दखलंदाजी रही है। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई सरकारों को बेशक सस्ती लोकप्रियता दिला सकती है, न्याय नहीं। महाराजगंज जिले में सड़क के फोर लेन की चौड़ीकरण के संबंध में एक व्यक्ति के मकान गिराने के लेकर कोर्ट ने काफी तीखी टिप्पणी दी और उत्तर प्रदेश सरकार पर 25

लाख का जुर्माना भी लगाया। हालांकि यह विकास कार्यों के लिए की गई कार्रवाई थी। इसमें सरकार की वह मंशा नहीं थी कि किसी अपराधी का घर गैरकानूनी अवैध कब्जा की बात कहकर गिराई गई हो। फिर भी कोर्ट ने पीड़ित की बात सुनी। इस तरह के अतिक्रमण हटाने के भी कायदे-कानून बने हुए हैं। उनका पालना किए गए बगैर सीधे बुलडोजर दौड़ा देना, अन्याय ही कहा जाएगा। ऐसे मामलों की भी कमी नहीं है, जहां आम आदमी की सम्पत्ति को अतिक्रमण के नाम पर ढहा दिया जाता है, वहीं रसुखदारों की तरफ प्रशासन की आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होती।

देश का शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जहां, प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण तोड़ने में सरकार और प्रशासन ने उदाहरण पेश किए होंगे। सरकार और प्रशासन प्रभावशाली लोगों के सामने कैसे नतमस्तक हो जाते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नोएडा के दिवन टावर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सुपरेटेक के नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपैक्स और सियान टॉवर्स को अवैध ठहराया था। दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश दिया। जबकि इस मामले में सरकार और नोएडा ऑथरिटी सब कुछ जानते हुए भी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहे। नोएडा ऑथरिटी की भी इस ध्वस्तिकरण पर निगरानी करने और रिपोर्ट अदालत को देने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के कुछ महीनों बाद बाद दिवन टावर को ढहा दिया गया।

बुलडोजर एक्शन लेने वाली सरकार और प्रशासन को यह पहले से ही पता था कि ये टावर नियमों के विपरीत बनाए गए हैं। इसके बावजूद शासन-प्रशासन में बैठे जिम्मेदार आखें मूंदे बैठे रहे। यहां बुलडोजर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसकी उपेक्षा ऐसे ही नहीं की गई।



इसमें भारी भ्रष्टाचार की गंध चारों तरफ से आ रही थी, किन्तु अदालत के फैसले से पहले किसी ने इसकी परवाह नहीं की, वहीं कमजोर के मामले में बुलडोजर एक्शन लेने में फुर्ती दिखाई जाती है। देश में भूमिाफिया और बिल्डर की शासन-प्रशासन से मिलीभगत के किस्से आम हैं।

देश के महानगर से लेकर छोटे शहरों में अतिक्रमणों की बाढ़ आई हुई है। ये अतिक्रमण एक दिन में नहीं हुए। अतिक्रमियों ने सार्वजनिक सुविधा के क्षेत्र तक नहीं छोड़े। देश में शायद ही ऐसी कोई सड़क या फुटपाथ होगा, जहां अतिक्रमण ने पांव नहीं पसारें। वन क्षेत्र हो या गोचर भूमि, यहां तक की तालाब, नदियों और झीलों के बहाव क्षेत्र भी अतिक्रमियों की भेंट चढ़

गए, किन्तु शासन-प्रशासन की तंद्रा भंग नहीं हुई। ये तभी जागते हैं जब अदालतों का डंडा चलता है। इन अतिक्रमियों के निर्माण पर बुलडोजर चलाने से सब कतराते हैं। इसका उदाहरण जयपुर का रामगढ़ बांध है। कभी बरसाती जल से सरोबार रहने वाला यह प्रसिद्ध बांध अतिक्रमियों का शिकार हो गया। कभी जयपुर की लाइफ लाइन माने जाने वाला यह बांध कई दशकों से सूखा पड़ा है। देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं जहां अतिक्रमियों ने प्राकृतिक स्रोतों को ही निगल लिया। यहां तक खनन करके की पहाड़ के पहाड़ गायब कर दिए। अरावली की पहाड़ी श्रृंखला इसका भ्रष्टाचार और लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। अतिक्रमण के मामले में वोट की

राजनीति की बदौलत ही छोटे-बड़े शहरों में अवैध कच्ची-पक्की बस्तियां तक बस गईं। ये अतिक्रमण सालों-साल चलते रहे हैं, किन्तु नेता-अफसरों के गठजोड़ के कारण इन्हें जड़ से खत्म नहीं किया जा सका। दरअसल बुलडोजर चलना तो ऐसे अतिक्रमणों पर चाहिए, जिसने देश के आम लोगों को पैदल चलना तक दुभर कर रखा है। इनके बजाए सिर्फ चुनिंदा अतिक्रमियों को अपराधी बता कर बुलडोजर चलवाना सरकारों की बदनीयति को ही उजागर करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकारों को सबक लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह कहीं नहीं कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, बल्कि वैधानिक प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया है।

- :सौजन्य :-

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



हीरो मोटोकॉर्प एक साल के भीतर सर्ज एस32 ईवी का करेगी उत्पादन शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

हीरो मोटोकॉर्प द्वारा निर्मित ऑल-इलेक्ट्रिक सर्ज 32 एक साल के भीतर सीरीज उत्पादन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यह अनुा वाहन जो दोपहिया और तिपहिया वाहनों को जोड़ता है, अब नव निर्मित एल2/एल5 श्रेणी के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि हीरो मोटोकॉर्प को प्रति वर्ष 10,000 इकाइयों की मामूली क्षमता का अनुमान है और यह मॉडल 2025 के मध्य तक बाजार में लॉन्च के लिए तैयार हो सकता है।

इस महीने की शुरुआत में इटली के मिलान में आयोजित EICMA 2024 मोटरसाइकिल व्यापार मेले के दौरान हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक डॉ. पवन मुंजाल ने कहा र पहली बार दुनिया भर में और भारत में अब हमें इन वाहनों को सड़क पर लाने के लिए इनको पंजीकृत करने की सरकार से अनुमति मिल गई है। दोनों के पास अलग-अलग पंजीकरण प्लेट होगी लेकिन एक बार जब स्कूटर तीन पहिया वाहन में चला जाता है, तो यह एक एकीकृत वाहन बन जाता है। इसलिए यह 'एकजुट होकर खड़े हैं' है। जब मैं अपने परिवार के साथ बाहर जाना चाहता हूँ, तो हमें तीन पहिया वाहन की आवश्यकता होती है और जब मुझे डिलीवरी के लिए केवल दोपहिया वाहन की आवश्यकता होती है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है।"

पंजीकरण के लिए इसे प्रमाणित करवाने के लिए सर्ज और हीरो मोटोकॉर्प को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर एस32 के लिए एक नई पंजीकरण श्रेणी बनानी पड़ी। इसे 'एल2-5' कहा जाता है, इसे रती पहियों वाले मोटर वाहन के 2-व्हीलर-3-व्हीलर कॉम्बी मॉड्यूल के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि श्रेणी एल2 के दो-पहिया

लॉन्च से पहले होण्डा ने जारी किया एक्टिवा इलेक्ट्रिक का नया टीजर, मीटर से लेकर रेंज तक की मिली जानकारी



परिवहन विशेष न्यूज

जापानी वाहन निर्माता Honda की ओर से जल्द ही नए स्कूटर को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी की जा रही है। नए स्कूटर को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लाया जाएगा। कंपनी के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च (Honda Activa Electric) से पहले सोशल मीडिया पर नया टीजर (Activa teaser) जारी किया गया है। टीजर में किस तरह की जानकारी मिल रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जापानी दो पहिया वाहन निर्माता Honda Motorcycle And Scooter India (HMSI) की ओर से कई सेगमेंट में बाइक्स और स्कूटर को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से जल्द ही इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपने पहले उत्पाद को लाने की तैयारी की जा रही है। लॉन्च से पहले होंडा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया टीजर जारी किया है। जारी हुए नए टीजर में क्या जानकारी मिल रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Honda Activa Electric का नया टीजर जारी

होंडा स्कूटर की ओर से जल्द ही EV सेगमेंट में अपने पहले उत्पाद के तौर पर Honda Activa Electric को लॉन्च (Honda EV launch) कर दिया जाएगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने अपने स्कूटर का नया Teaser जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी हुए टीजर में कई तरह की जानकारी को दिया गया है।

टीजर से मिली यह जानकारी

सोशल मीडिया पर होंडा के आधिकारिक अकाउंट पर कुछ सेकेंड का वीडियो टीजर (Activa Electric teaser) जारी किया गया है। जिसमें दो तरह के स्पॉटलीमोटर को दिखाया गया है। जिसको पूरी तरह से डिजिटल रखा गया है। इसके साथ ही इसमें स्कूटर की रेंज और राइडिंग मोड्स की जानकारी मिल रही है। खास बात यह है कि जारी किए गए नए टीजर में दूसरी स्क्रीन में एक मोटरसाइकिल की इमेज दिखाई दे रही है, जिसके बाद यह संभावना बढ़ रही है कि कंपनी की ओर से एक्टिवा के साथ ही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को भी लाया जा सकता है। टीजर में

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने केरल में ईवी रिटेल उपस्थिति का किया विस्तार

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (टीपीईएम) ने केरल में दो विशेष टाटा ईवी रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया है, जो राज्य में ईवी के बढ़ते चलन को दर्शाता है। कन्नूर और त्रिशूर में स्थित नई सुविधाएं अगस्त 2024 में राज्य में दो समान स्टोर लॉन्च करने के बाद हैं।

थोड़ाड़ा में स्थित कन्नूर स्टोर 5,200 वर्ग फीट में फैला है और यह दक्षिण भारत का पहला ईवी-एक्सक्लूसिव रिटेल और सर्विस सेंटर है। 10-बे सर्विस वर्कशॉप से सुसज्जित, यह सुविधा एक व्यापक ग्राहक अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है। त्रिशूर में,

कुट्टानेल्लूर में नया रिटेल स्टोर रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 544 के पास स्थित है और इसमें 7,000 वर्ग फीट का शोरूम है। त्रिशूर स्टोर का निर्माण एक पुरानी सुविधा को फिर से तैयार करके और आधुनिक बनाकर किया गया है।

ईवी-एक्सक्लूसिव स्टोर स्थापित करने का टीपीईएम का कदम ईवी स्वामित्व अनुभव को बेहतर बनाने पर इसके रणनीतिक जोर को दर्शाता है, जिसमें बिक्री और सेवा सहायता की पेशकश की जाती है। ईवी के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में केरल की स्थिति टाटा ईवी स्टोर्स की तेजी से स्थापना से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है।



ईवी ट्रैक्टरों को बढ़ावा देना यूपी सरकार के एजेंडे में अगला कदम

परिवहन विशेष न्यूज

अब सभी की निगाहें इलेक्ट्रिक वाहन ट्रैक्टरों- ईवी ट्रैक्टरों पर हैं, क्योंकि खेती में ऊर्जा-कुशल तकनीकों को बढ़ावा देना राज्य सरकार का अगला एजेंडा है।

भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) ने ईवी ट्रैक्टरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सीआईआई एग्रीटेक इंडिया - कृषि भारत 2024 में उद्योग विशेषज्ञों और इन्वेस्ट यूपी को एक साझा मंच पर एक साथ लाया।

विशेषज्ञों ने कहा कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था, उद्योगों को बढ़ावा देने पर इसका ध्यान और नई ईवी नीति राज्य में ईवी ट्रैक्टरों को पेश करने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि निदेशक जितेंद्र कुमार तोमर ने पर्यावरण के अनुकूल खेती समाधानों में बदलाव को आसान बनाने में सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी योजनाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों के बीच ईवी ट्रैक्टरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया।

इस अवसर पर उपस्थित इन्वेस्ट यूपी के ईवी पॉलिसी सेल के अतिरिक्त महाप्रबंधक अभित कुमार मिश्रा ने उपस्थित लोगों को



ईवी चार पहिया और दो पहिया वाहनों की विनिर्माण लागत को कम करने और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नीतियों और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी। मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों को न केवल पर्यावरण के अनुकूल बल्कि कृषि के भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए अत्यधिक कुशल उपकरण के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

विशेषज्ञों ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर निर्माण और अपनाने के विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की ईवी समर्थक नीतियों पर भी प्रकाश

ओडिसी इलेक्ट्रिक कंपनी देगी 40000 वाहन जिप इलेक्ट्रिक को

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय दोपहिया ईवी कंपनी ओडिसी इलेक्ट्रिक ने निवेश करते हुए सौदा हासिल किया है। इस निवेश सौदे के तहत कंपनी जिप इलेक्ट्रिक को 40000 इलेक्ट्रिक वाहन देगी। कंपनी ने अपने राष्ट्रीय विस्तार के तहत इस निवेश सौदे की योजना तैयार की है। कंपनी अगले 3 सालों में जिप इलेक्ट्रिक को चालीस हजार इलेक्ट्रिक वाहन देगी। कंपनी ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की संभावनाओं और तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए यह निवेश सौदा किया है। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर कई घोषणाएं की जा रही हैं। अलग-अलग ऑटो मैनुफैक्चरिंग कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस कर रही हैं।

कंपनी की बी2बी पहुंच और डीलरशिप विस्तार नेटवर्क को बढ़ाने की उम्मीद में यह निवेश किया गया है। उत्पादन और वितरण क्षमताओं का विस्तार करके ओडिसी इलेक्ट्रिक का लक्ष्य लोगों

की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाना है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नैमिन वारा ने कहा कि ओडिसी इलेक्ट्रिक में नया निवेश एक महत्वपूर्ण क्षण है। जिप इलेक्ट्रिक को गहरी उद्योग विशेषज्ञता और बड़े के विद्युतीकरण की दृष्टि हमारी राष्ट्रव्यापी विस्तार योजनाओं को काफी तेज करेगी, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) और उपभोक्ता मांग को रेखांकित करती है।

जिप इलेक्ट्रिक के सह-संस्थापक और सीईओ आकाश गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि कंपनी को अगले 2-3 वर्षों में डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 2 लाख ईवी तैनात करने की उम्मीद है। ओडिसी इलेक्ट्रिक में हमारा निवेश दर्शाता है कि हम कंपनी के विजन, उत्पाद की गुणवत्ता और विकास में कितना विश्वास करते हैं।



जनवरी से सितंबर 2024 के दौरान दुनियाभर में हुई 6.5 करोड़ कारों की बिक्री, भारत का रहा कैसा हाल

परिवहन विशेष न्यूज

भारत सहित दुनियाभर में हर महीने लाखों की संख्या में कारों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2024 के बीच नौ महीनों के दौरान कुल कितनी कारों की बिक्री (Global Car Sales 2024) की गई है। Top-3 में कौन कौन से देश शामिल हैं और इस लिस्ट में भारत (India Car Sales 2024) का स्थान कहां पर है।

नई दिल्ली। भारत सहित दुनियाभर में बड़ी संख्या में कारों की बिक्री की जाती है। हर महीने लाखों की संख्या में लोग कारें खरीदते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 के पहले नौ महीनों के दौरान दुनियाभर में कितनी कारों (Global Car Sales 2024) की बिक्री हुई है। Top-3 में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। भारत का नंबर (India Car Sales 2024) कहां आया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कितनी हुई बिक्री

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनियाभर में इस साल बड़ी संख्या में कारों की बिक्री हुई है। जानकारी के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2024 के बीच कुल 6.5 करोड़ यूनिट्स कारों को खरीदा गया है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो यह बढ़ोतरी सिर्फ 0.3 फीसदी ज्यादा है। बीते साल भी इसी अवधि के दौरान करीब छह करोड़ से ज्यादा कारों की बिक्री हुई थी।



इस देश में रही सबसे ज्यादा मांग

रिपोर्ट्स के मुताबिक भले ही दुनियाभर में 6.5 करोड़ यूनिट्स कारों की बिक्री हुई है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा योगदान चीन का है। अकेले चीन में ही एक तिहाई कारों की बिक्री की गई है, जिस कारण इस लिस्ट में पहला नंबर चीन का है। जानकारी के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2024 के बीच चीन में 2.14 करोड़ कारों की बिक्री हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह संख्या 3.7 फीसदी ज्यादा है।

Top-3 में शामिल हुआ भारत

साल के पहले नौ महीनों में कारों की बिक्री के मामले में भारत ने भी Top-3 में अपनी जगह बनाई है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर जापान रहा। जहां इसी अवधि के दौरान 57.12 लाख यूनिट्स

की बिक्री हुई है। वहीं तीसरे नंबर पर भारत रहा। भारत में इस दौरान कुल 36.14 लाख यूनिट्स कारों की बिक्री की गई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भारत में 3.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं दूसरे नंबर पर रहने वाले जापान में 8.7 फीसदी की गिरावट आई है।

भारत के बाद अमेरिका और जर्मनी का नंबर

Top-3 में भारत का नंबर रहा, लेकिन अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में कारों की बिक्री में कमी आई है। अमेरिका में साल के पहले नौ महीनों के दौरान 26.9 फीसदी कारों की बिक्री की गई है और पांचवें नंबर पर जर्मनी रहा है, जहां जनवरी से सितंबर के बीच 23.04 लाख कारों की बिक्री हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में

पिछले साल के मुकाबले इस साल 4.2 और जर्मनी में 0.4 फीसदी की कमी आई है।

किस कंपनी की कारों की रही सबसे ज्यादा मांग

जापान की वाहन निर्माता टोयोटा दुनिया के कई देशों में अपनी कारों को ऑफर करती है। कंपनी ने जनवरी से सितंबर के बीच 27.4 लाख कारों की बिक्री की है और लिस्ट में पहले नंबर को हासिल किया है। इसके बाद 21.8 लाख यूनिट्स के साथ Volkswagen का नंबर रहा। तीसरे नंबर पर साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Hyundai रही जिसकी 17.8 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई है। इसके बाद स्टेलैस, जनरल मोटर्स, बीवाइडी, फोर्ड, होंडा, गिली और निसान का नंबर रहा है।

आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन ने जॉब के लिए बदले नियम, पहले शादीशुदा महिलाओं को नहीं दे रही थी नौकरी

परिवहन विशेष न्यूज आइफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फॉक्सकॉन ने भारत में अपनी असेंबली लाइन में कर्मचारियों की भर्ती करने के नियमों में बदलाव किया है। दरअसल समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जून में एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी शादीशुदा महिलाओं को काम पर नहीं रखती है और उसके वेंडर्स नौकरी के विज्ञापन में भी इस का जिक्र करते हैं। इस पर फॉक्सकॉन की काफी किरकिरी हुई थी। नई दिल्ली। अमेरिकी टेक दिग्गज एपल के स्प्लायर फॉक्सकॉन (Foxconn) ने भारत में iPhone असेंबली कर्मचारियों की भर्ती करने वाले रिक्रूटर्स को कई नए निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक, नौकरी के इशतिहार में उम्र, लिंग और वैवाहिक मानदंड के साथ मैन्युफैक्चरर का नाम हटाने का आदेश दिया है। वैश्विक समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 25 जून को एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें पाया गया था कि फॉक्सकॉन ने अपने भारत वाले iPhone असेंबली प्लांट में विवाहित महिलाओं को नौकरियों से बाहर रखा। हालांकि, इसने ज्यादा प्रोडक्शन वाली अवधि के दौरान इस नियम में ढील दी और शादीशुदा महिलाओं को भी काम पर रखा।	क्या है नौकरी विज्ञापन का पूरा मामला चेन्नई के पास श्रीपेरंबदूर में iPhone फैक्ट्री में फॉक्सकॉन हजारों महिलाओं को रोजगार देती है। इस असेंबली-लाइन में कंपनी श्रमिकों की भर्ती के लिए थर्ड पार्टी वेंडर्स को आउटसोर्स करती है। ये एजेंट उम्मीदवारों की तलाश करते हैं और उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। आखिर में फॉक्सकॉन उनका इंटरव्यू और सेलेक्शन करती है। जून की कहानी के लिए रॉयटर्स ने जनवरी 2023 और मई 2024 के बीच फॉक्सकॉन के इंडियन हायरिंग वेंडर के पोस्ट के किए नौकरी विज्ञापनों की समीक्षा की। इसमें कहा गया था कि सिर्फ खास आयु की अविवाहित महिलाएं ही स्मार्टफोन असेंबली में जॉब रोल के लिए पात्र हैं, जो Apple और Foxconn की भेदभाव-विरोधी नीतियों का उल्लंघन है। इस रिपोर्ट के छपने के बाद फॉक्सकॉन की काफी किरकिरी हुई। इसके बाद फॉक्सकॉन एचआर अधिकारियों ने कई भारतीय वेंडर्स को नौकरी के विज्ञापन बदलने के लिए कहा। उन्हें चेतावनी दी गई कि आगे किसी के किसी भी इशतिहार में वे फॉक्सकॉन के नाम का इस्तेमाल न करें, नहीं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने वेंडर्स को मीडिया से बात न करने के लिए भी कहा। अब वैवाहिक स्थिति का जिक्र नहीं	
--	---	--

कितने समय में म्यूचुअल फंड्स में पैसे होंगे डबल

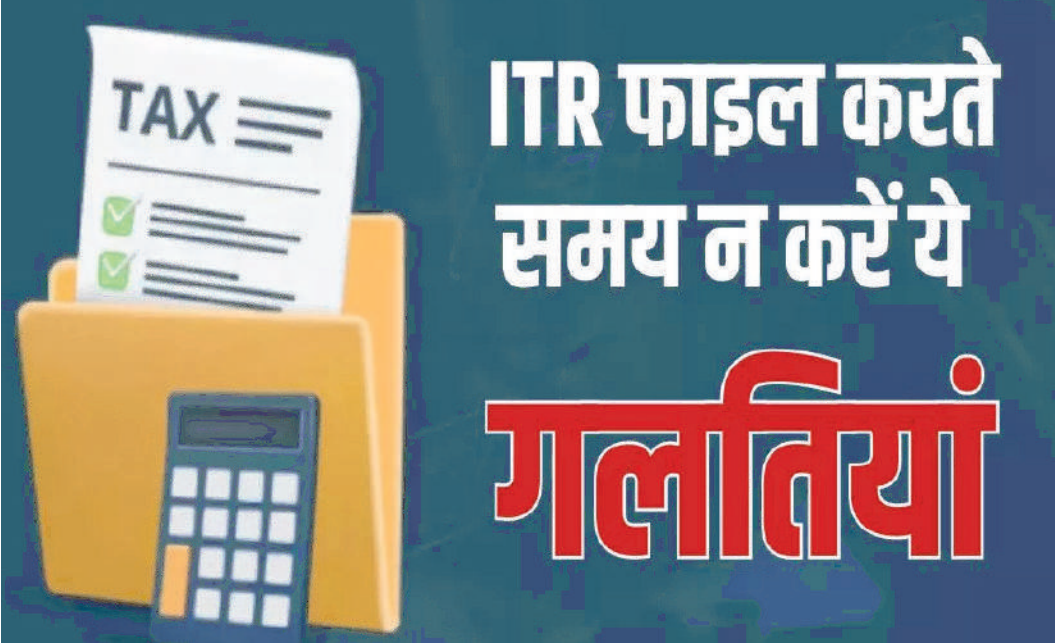
म्यूचुअल फंड निवेश के सबसे लोकप्रिय माध्यमों में से एक है। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं लेकिन ज्यादातर निवेशक इक्विटी और डेट MF को पसंद करते हैं। कई निवेशकों के मन में ये सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कैसे करें उनके लिए कौन-सा प्लेटफॉर्म सही है किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। नई दिल्ली। सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अगर आप बाजार को लगातार ट्रेक नहीं कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। क्योंकि आपके निवेश को एक फंड मैनेजर, मैनेज करता है। हालांकि कई निवेशकों के मन में ये सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कैसे करें, उनके लिए कौन-सा प्लेटफॉर्म सही है, किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में हमने इन्हीं सवालों के जवाब जानने कि कोशिश की। इन सभी मुद्दों पर हमसे बातचीत की Avdhesh Garg, Founder & CEO, Confidence Investment ने। Mutual Fund कितने प्रकार के होते हैं? इस सवाल के जवाब में Avdhesh Garg ने बताया कि म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से दो	तरीके के होते हैं। एक Equity Mutual Fund और दूसरा Debt Mutual Fund। इन दोनों में अलग-अलग तरह के जोखिम जुड़े होते हैं। और दोनों अलग-अलग तरह से काम करते हैं। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहां पूरा देख सकते हैं। कितना होता है जोखिम? Equity Mutual Fund में आपके सारे पैसे शेयर बाजार में लगाए जाते हैं। जिसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का रिस्क होता है। जबकि Debt Mutual Fund में आपके पैसे उधार में लगाए जाते हैं जिसमें Interest Rate का रिस्क होता है। Debt Mutual Fund में ब्याज दरें बढ़ने से आपको रिटर्न कम होने का खतरा होता है जबकि ब्याज दरें कम होने से रिटर्न बढ़ने का उम्मीद होती है। क्या होता है Rule No 72? इस रूल के जरिए आप ये जान सकते हैं कि आपके पैसे कितने सालों में दोगुने होंगे। इसके लिए आपको जितना भी रिटर्न मिल रहा है उसे 72 से भाग कर दें। गर्ग ने एक उदाहरण के जरिए बताया कि “जैसे मान लीजिए आपको एक साल में 12% का रिटर्न मिल रहा है तो आप 12/72 करेंगे यानी कि 6 सालों में पैसे डबल। इसके साथ ही ध्यान रखें कि जितना ज्यादा Compound Annual Growth Rate यानी CAGR होगा उतनी जल्दी आपका पैसा डबल होगा।”
---	---

शेयर मार्केट में मंदी का दौर, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्यों नहीं है डरने की बात?

परिवहन विशेष न्यूज भारतीय शेयर बाजार अभी सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। इससे निवेशक काफी नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह निराशा होने का नहीं बल्कि निवेश के लिए अच्छे मौके तलाशने का वक्त है। इस तरह की गिरावट 4 से 5 साल में एक बार ही आती है और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छे शेयरों को सस्ते में खरीदने का मौका मिल सकता है। नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है। दोनों प्रमुख सूचकांक यानी सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से करीब 10 फीसदी गिर चुके हैं। इस करेक्शन की कई वजहें हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FIIs) लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनियों के	तिमाही नतीजे काफी आ रहे हैं। वैश्विक अस्थिरता भी बढ़ी है। शेयर मार्केट में हालिया गिरावट से निवेशकों का भरोसा भी डगमगाया है। लेकिन, एक्सपर्ट का मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डरने की कोई बात नहीं है। बस कोई नया दांव लगाने से पहले मार्केट में स्थिरता आने का इंतजार करना चाहिए। आइए जानते हैं कि भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट की क्या वजह है और निवेशकों को फिलहाल क्या करना चाहिए। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था खराब कर रही है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोनाकाल की मंदी के बाद जोरदार तेजी देखने को मिली। पिछले कुछ तिमाहियों को भी देखें, तो जीडीपी ग्रोथ 7 से 8 फीसदी के बीच रही है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की तेजी के बाद स्लोडाउन आना आम बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था साइकिलिकल स्लोडाउन से निकल रही है। इसमें स्ट्रक्चरल स्लोडाउन जैसी बात नहीं है। खपत धीरे-धीरे पटरी पर आ जाएगी और इकोनॉमी फिर से बढ़ने लगेगी। निवेशकों को इन्वेस्टमेंट का मौका कब
---	--



इस जानकारी को छिपाने पर लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना, आयकर विभाग ने किया आगाह



परिवहन विशेष न्यूज कई बार करदाता जाने या फिर अनजाने में आईटीआर फाइल करते वक्त कुछ जानकारीयों को गैर-जरूरी मानकर छिपा लेते हैं। इनमें विदेश में संपत्ति जैसी डिटेल् भी होती है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई करदाता विदेश में स्थिति संपत्ति या अर्जित आय की जानकारी नहीं देता तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय सभी	जानकारियां ठीक-ठीक देनी चाहिए। लेकिन, कई बार करदाता कुछ जानकारीयों को गैर-जरूरी मानकर जाने-अनजाने में छिपा लेते हैं। ऐसा करना काफी महंगा पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए करदाताओं पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को आगाह किया है कि आईटीआर में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेश में अर्जित आय की जानकारी नहीं देने पर काला धन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। डिपार्टमेंट ने एक सार्वजनिक परामर्श भी जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाता असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपने आईटीआर में ऐसी जानकारी दर्ज करें। किस तरह की कमाई की देनी	होगी जानकारी परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि भारत के निवासी के लिए विदेशी परिसंपत्ति में बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिक अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, अभिरक्षक खाता, इक्विटी और ऋण हित, ट्रस्ट जिसमें व्यक्ति ट्रस्टी है, सेटलर का लाभार्थी, हस्ताक्षर प्राधिकारी वाले खाते, विदेश में रखी गई कोई पूंजीगत परिसंपत्ति आदि शामिल हैं। विभाग ने कहा कि इस मानदंड के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को अपने आईटीआर में फॉरेन असेट (एफए) या विदेशी स्रोत से आय (एफएसआई) अनुसूची को अनिवार्य रूप से भरना होगा, भले ही उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो या विदेश में संपत्ति प्रकट स्रोतों से अर्जित की गई हो। करदाताओं को मेल भेजेगा आयकर विभाग	इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए प्रशासनिक निकाय-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि अभियान के तहत वह उन करदाताओं को सूचनात्मक एसएमएस और ईमेल भेजेगा, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है। इससे उन्हें अपनी गलती को सुधारने का मौका मिल सकेगा और वे नियमों के मुताबिक जरूरी जानकारी दे सकेंगे। यह एसएमएस और ईमेल ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाएगा, जिनकी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से पहचान की गई है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ये व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रख सकते हैं या विदेशी क्षेत्राधिकार से आय प्राप्त कर चुके हैं। देर से एवं संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
--	---	--	---

आईजीएल, एमजीएल और अदाणी टोटल गैस के शेयरों में बड़ी गिरावट, क्या अब बढ़ेंगे सीएनजी के दाम?

GAIL ने इंद्रप्रस्थ गैस महानगर गैस और अदाणी टोटल गैस के आवंटन में क्रमशः 20 18 और 13 फीसदी की कटौती की है। इससे इन तीनों कंपनियों के मुनाफे पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। दोपहर करीब 12 बजे तक इंद्रप्रस्थ गैस 18 महानगर गैस 14 और अदाणी टोटल गैस में 2 फीसदी की गिरावट आई थी। इससे ब्रोकरेज फर्म CNG के दाम में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। नई दिल्ली। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL), महानगर गैस लिमिटेड (MGL) और अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas Ltd.) के शेयरों में आज यानी सोमवार (18 नवंबर) को भारी गिरावट गिरावट देखने को मिल रही है। IGL और MGL शुरुआती कारोबार में 15 फीसदी तक फिसल गए थे। वहीं, अदाणी टोटल गैस में करीब 4 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।	IGL और MGL में गिरावट की वजह GAIL (इंडिया) ने एलान किया कि उसने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए गैस आवंटन में 13 से 20 फीसदी की कटौती कर दी है। इससे IGL और MGL के साथ अदाणी टोटल गैस जैसी कंपनियों के मार्जिन पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। सिटी गैस कंपनियों को उनकी CNG सेल्स वॉल्यूम जरूरतों के लिए 6.5 डॉलर/mmbtu (मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट) के फिक्स्ड प्राइस पर घरेलू गैस का आवंटन होता है। अगर घरेलू गैस का आवंटन घटेगा, तो इसका सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ेगा। गैस आवंटन में कितनी कटौती हुई? GAIL ने इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस और अदाणी टोटल गैस के आवंटन में क्रमशः 20, 18 और 13 फीसदी की कटौती की है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में ऑथल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने भी आवंटन में 16-20 फीसदी की रेंज में कटौती की थी। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का मानना है कि 2025 के मध्य तक सिटी गैस कंपनियों का घरेलू गैस आवंटन जीरो हो जाएगा।	कटौती का क्या होगा असर? ONGC ने अपनी पहली कटौती का ऐलान किया था, तो एमके रिसर्च ने अनुमान लगाया था कि इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस के मार्जिन पर 1.4-1.5 रुपये/scm का नेगेटिव असर पड़ेगा। अब यह बढ़कर 2.7-3 रुपये/scm हो गया है। ब्रोकरेज जेफरीज के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 में इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस और गुजरात गैस के प्रति यूनिट EBITDA मार्जिन में 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये प्रति/स्qm की बड़ी गिरावट आ सकती है। CNG कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान IIFL सिक्कोरिटीज, एमके रिसर्च और जेफरीज का कहना है कि गैस कंपनियों को अपना मार्जिन बनाए रखने के लिए CNG का दाम बढ़ाना पड़ेगा। जेफरीज के मुताबिक, CNG की रिटेल कीमतों में 10 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, सिस्टेमीटिक्स का अनुमान 6-8 रुपये प्रति किलो और एमके रिसर्च 6.3-6.4 रुपये प्रति किलो बढ़ने का अनुमान है। हालांकि, ब्रोकरेज का मानना है कि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते कीमतों में जल्द बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे निकट अवधि में कंपनियों के लिए मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है।
---	--	--

